[2017] 7 एस. सी. आर. 825

पद्मिनी महेंद्रभाई गड्डा

बनाम

गुजरात राज्य

[आपराधिक अपील संख्या 40/2007]

17 जुलाई, 2017

[एन. वी. रमन्ना और प्रफुल्ल सी.पंत, जे. जे.]

दंड संहिता 1860- धारा 201- अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना- धारा 201 के घटक- अभियोजन पक्ष का मामला है कि मुख्य आरोपी ने अपीलकर्ता के साथ अपने अवैध संबंध के कारण, फरार आरोपी की मदद से अपीलकर्ता के पति की हत्या की, और यह कि अपीलकर्ता चुप रही और मुख्य आरोपी के साथ फरार हो गई- मुख्य अभियुक्त को धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया, हालांकि, अपीलकर्ता को केवल धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई- उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपीलकर्ता की सजा को सात साल तक बढ़ा दिया- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: एन. वी. रमन्ना, जे के अनुसार: धारा 201 के तहत आरोप पर विचार करते समय, अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी ने सबूतों को गायब करके अपराधी को बचाने में सक्रिय रूप से भाग लिया- चुप रहना और आरोपी के साथ फरार रहना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना

न तो साक्ष्य प्रदान करेगा और न ही उस अंतर को भरेगा जो धारा 201 के तहत घटकों को साबित करने के लिए आवश्यक है- निचली अदालतों का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता ने चुप रहकर परोक्ष रूप से हत्या के सबूत गायब करने के अपराध को बढ़ावा दिया, स्वीकार नहीं किया जा सकता- निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को अनुमानों और धारणाओं पर दोषी ठहराया, इस प्रकार, धारा 201 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है- अपीलकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सज़ा पहले ही भुगत चुकी है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया जाता है- पी. सी. पंत जे. के अनुसार अपीलकर्ता ने अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी दी, इस प्रकार, धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप के संबंध में निचली अदालतों द्वारा उसे दोषी ठहराया गया- अपीलकर्ता पहले ही मुकदमे/अपील की अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक कारावास की सजा काट चुका है; कि वह साठ साल की है, और घटना हुए तेईस साल बीत चुके हैं, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को घटाकर दो साल की सश्रम कारावास और जुर्माना कर दिया जाता है। मतभेद को देखते हुए मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया।

एन.वी. रमन्ना, जे. के अनुसार: अपील को अनुमति प्रदान करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 1.1 यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य मजबूत, ठोस और अकाट्य होने चाहिए, जिससे केवल यही निष्कर्ष निकले कि अपराध केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया होना चाहिए और इससे कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। [पैरा 12] (834-जीएच; 835-ए)

1.2 आपराधिक मुक़दमा कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप पर विचार करते समय, अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी ने सबूतों को गायब करने में और अपराधी को बचाने में सक्रिय

रूप से भाग लिया। धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए, यह आवश्यक है कि आरोपी के अपराध की ओर इशारा करने वाले सभी तत्व संतुष्ट हों और केवल संदेह पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को कभी भी संभावनाओं के आधार पर या धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। [पैरा 19] [838-बी-डी]

1.3 विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायालय ने अपीलकर्ता को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि वह किसी भी तरह से अपराध में शामिल नहीं है। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि हत्या के अपराध के उक्त सबूत को गायब करने में आरोपी नंबर 2 की भागीदारी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चुप रहकर उसने अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा दिया है। यह देखा गया कि या तो डर के कारण या उसे ज्ञात किसी कारण से, वह चुप रही और धारा 201 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध को बढ़ावा दिया या सहायता की। [पैरा 21) [839-ई-जी]

1.4 एकमात्र चश्मदीद गवाह 'ए', मृतक की बेटी और अपीलकर्ता के साक्ष्य को छोड़कर अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। चश्मदीद गवाह ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता रो रही थी और वह आरोपी नंबर 1 से उसके पति को न मारने की प्रार्थना कर रही थी। उसने जिरह में आगे कहा कि आरोपी नंबर 1 ने अपीलकर्ता को चुप रहने और कोई परेशानी न करने के लिए कहा क्योंकि आरोपी नंबर 1 और फरार आरोपी वापस आ जाएंगे। आरोपी नंबर 2 ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में भी यही बात दोहराई। [पैरा 22) [839-जी-एच; 840-ए)

1.5 निचली अदालतों के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चुप रहकर आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से हत्या के सबूतों को गायब करने के अपराध को बढ़ावा दिया। चुप रहना और आरोपी नंबर 1 के साथ फरार रहना और एक जगह से दूसरी जगह जाने से सबूत नहीं मिलेंगे या उस कमी को पूरा नहीं किया जाएगा जो आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध को साबित करने के लिए जरूरी है। विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से पाया कि आरोपी नंबर 2 का सबूतों के गायब होने से कोई लेना-देना नहीं था और मकसद के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना, उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया। वास्तव में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय मकसद के संबंध में कोई तर्क नहीं दे सका जो कि आरोपी पर आरोप तय करने का महत्वपूर्ण पहलू है। चुप रहने के तथ्य के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य और अपीलकर्ता के बयान से कारण सामने आ रहा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। [पैरा 25) [840- एफ-एच; 841-ए)

1.6 विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की आपराधिक मंशा के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाले बिना अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर गलती की। विशेष रूप से, जब विचारण न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो उसे कल्पनाओं और धारणाओं के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जब अपीलकर्ता और आरोपी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, तो उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सजा बढ़ाने के लिए धारा 377 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने सज़ा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया। [पैरा 27] [842-ए-सी]

1.7 इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि सजा को अपराध के अनुरूप होने देना सजा नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। सज़ा पर्याप्त रूप से उचित होनी चाहिए, दोषी की प्रकृति के अनुपात में होना एक महत्वपूर्ण कारक है। सजा देना विचारण न्यायालय के विवेक का मामला है और सामान्य परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय इस तरह के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वह तभी हस्तक्षेप करेगा जब उसे पता चलेगा कि न्याय का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का घोर दुरुपयोग हो रहा है और जहां सजा सुनाने वाले न्यायालय द्वारा विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय को दोषसिद्धि की अपील से मामले के गुण-दोष के आधार पर निपटाना होगा और एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि देकर सही किया था, तो उसे इस पहलू पर गौर करना होगा कि सजा आनुपातिक थी या नहीं। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से कि अपीलकर्ता हत्या करने में सक्रिय रूप से शामिल है और षड्यंत्र के संबंध में निष्कर्ष और विशेष रूप से, यह देखते हुए कि चूंकि राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है, इसलिए वह इससे निपटने की स्थिति में नहीं है। वही, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से सजा बढ़ा दी। उच्च न्यायालय के संपूर्ण तर्क को देखते हुए, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और वास्तव में उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा, लेकिन यह केवल सजा के पहलू से भिन्न था। सजा बढ़ाने और अपील खारिज करने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क धारा 302 या 120बी के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एक वैध और सही तर्क हो सकता है, जब राज्य ने दोषमुक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत की हो। लेकिन ऐसे तर्क के आधार पर अपीलकर्ता को धारा 201 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 201 के तहत अपराध को साबित करने के घटक पूरी तरह से अलग हैं। उसकी केवल चुप्पी से यह अनुमान नहीं

लगाया जा सकता कि उसने अपराध किया है। मौजूदा मामले में विचारण और अपीलीय न्यायालय दोनों ही मामले को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहे, उन्होंने धारणाओं पर अधिक भरोसा किया और धारणाओं के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया, जो स्थापित कानून के विपरीत है। [पैरा 28] [843-सी एच; 844-ए]

1.8 आम तौर पर, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में, जहां दोनों निचली अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए थे, यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन, मौजूदा मामले में दोनों निचली अदालतों ने, आईपीसी की धारा 201 के घटकों को संतुष्ट किए बिना, अपीलकर्ता को अनुमानों और धारणाओं पर दोषी ठहराया, जिससे इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। [पैरा 30) (844-बी-सी)

1.9 अभियोजन उचित संदेह से परे आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता/अभियुक्त संख्या 2 के अपराध को साबित करने में सक्षम नहीं है। अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा भुगत चुकी है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। [पैरा 31] (844-डी)

आनंद दगड़ू जाधव और अन्य बनाम रुक्मिणी बाई आनंद जाधव और एक अन्य (1993) पूरक 3 एस.सी.सी. 68; सौ. विजया उर्फ बाबी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003) 8 एस.सी.सी. 296; राघव प्रपन्न त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 74: [1963] एस.सी.आर. 239- संदर्भित

प्रकरण कानूनी संदर्भ

(1993) पूरक 3 एस.सी.सी. 68 का पैरा 9 संदर्भित

(2003) 8 एस.सी.सी. 296 का पैरा 18 संदर्भित

[1963] एस.सी.आर. 239 का पैरा 26 संदर्भित

प्रफुल्ल सी. पंत, जे. के अनुसार (आंशिक रूप से असहमत):

अपील को आंशिक अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: 1.1 यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने ही भाई पीडब्लू-3 (शिकायतकर्ता) को मृतक के बारे में गलत बयान देकर, और पीडब्लू-34 को शयनकक्ष से जुड़े बाथरूम (जहां शव छुपाया गया था) का उपयोग करने की अनुमति ना देकर, अपीलकर्ता ने अपराधी (ए-1) को बचाते हुए गलत जानकारी दी। इस प्रकार, उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप के संबंध में निचली अदालतों द्वारा सही रूप से दोषी ठहराया गया था। ए-2 के अपराध के बारे में अपने स्वयं के निष्कर्ष के विरुद्ध विचारण न्यायालय की कुछ टिप्पणियाँ इस न्यायालय के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, खासकर जब विचारण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय के फैसले में सहमति दी गई है और, इस प्रकार, अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से बरी नहीं किया जा सकता। [पैरा 15] [848-जी-एच; 849-ए]

1.2 प्रत्येक मामले में उस विशेष मामले के तथ्यों और सबूतों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए देखा जाना चाहिए कि उस मामले में किसी विशेष अपराध के घटक है या नहीं। [पैरा 15] [849-बी]

1.3 निचली अदालतों ने पारित आदेशों में यह निष्कर्ष निकालने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप की दोषी है। हालाँकि, सजा के संबंध में, उच्च न्यायालय ने ए-2 (अपीलकर्ता) को अधिकतम सजा सुनाई। रिकॉर्ड से यह बताया गया है कि अपीलकर्ता पहले ही

मुकदमे/अपील की अवधि के दौरान दो साल से अधिक कारावास की सजा काट चुकी है; कि वह साठ वर्ष की है और घटना की दिनांक से तेईस वर्ष बीत चुके हैं। इन परिस्थितियों में, चूंकि ए-1 को आईपीसी की धारा 201 के तहत दी गई सजा उसी आरोप के संबंध में अंतिम रूप ले चुकी है, इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ए-2 को बढ़ी हुई सजा देना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से ए-1 की तुलना में उक्त आरोप के संबंध में उसकी भूमिका को देखते हुए। आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ निचली अदालतों द्वारा दर्ज की गई सजा को बरकरार रखा गया है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम करके जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास में बदल दिया गया है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है। [पैरा 16, 17] [849-सी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 40/2007

आपराधिक अपील संख्या 833/1997 और आपराधिक अपील संख्या 833/1997 में आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1121/1998 में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.10.2001 से।

अपीलकर्ता की ओर से वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, निखिल गोयल, सौरिन ए शाह।

प्रतिवादी की ओर से डी. एन. रे, सुश्री हेमन्तिका वाही, सुश्री जेसल वाही।

न्यायालय के निर्णय और आदेश एन. वी. रमन्ना, जे. द्वारा पारित किए गए।

1. आपराधिक अपील संख्या 833/1997 और आपराधिक अपील संख्या 833/1997 में आपराधिक एम.ए. संख्या 1121/1998 में गुजरात उच्च न्यायालय,

अहमदाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 से व्यथित होकर अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष आया है।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि यहां अपीलकर्ता और महेंद्रभाई (मृतक) ने वर्ष 1981 में प्रेम विवाह किया था और उनके दो बेटियाँ हुईं। मृतक अहमदाबाद शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर पीएम हेल्थ क्लब के नाम और शैली में हेल्थ क्लब चला रहा था; एक नारणपुरा में और दूसरा अंबावाड़ी में। आरोपी नंबर 1 यानी किशोर ठक्कर को मृतक ने नारणपुरा स्थान पर काम करने के लिए नियुक्त किया था। समय बीतने के साथ, अपीलकर्ता (ए 2) ने किशोर ठक्कर (ए 1) के साथ विवाहेतर संबंध विकसित कर लिया और उसके परिणामस्वरूप, उन्होंने महेंद्रभाई (मृतक) को मारने की योजना बनाई। इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता ने अपराह्न 3:00 बजे मृतक के बारे में पूछताछ की, तो अपीलकर्ता ने उत्तर दिया कि मृतक बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। यह सुनकर शिकायतकर्ता को अपनी बहन के जवाब देने के तरीके पर संदेह हुआ। शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के साथ उस दिन शाम करीब 4 बजे अपीलकर्ता के घर गया और उससे कहा कि वह जाकर अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से वापस ले आए। जब वह झिझकते हुए घर से बाहर चली गई, तो उसने घर की तलाशी ली और पाया कि उसका जीजा बाथरूम में खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ था और ए 1 वहां मौजूद था। जैसे ही उसने ए 1 को पकड़ने की कोशिश की तो वह उसे धक्का देकर अर्धनग्न अवस्था में ही मौके से भाग गया। जबकि, अपीलकर्ता जो अपने बड़ी बेटी को स्कूल से वापस लाने गई थी, वह अपने घर वापस नहीं लौटी।

3. मृतक के साले की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी और 201 सपठित धारा 302 के तहत अपराध संख्या आईसीआर 759/1994 दर्ज किया [इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'आईपीसी']। घटना

स्थल पर पंचनामा कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अपराध की जांच करते हुए, पुलिस ने 23.01.1995 को एसटी बस स्टेशन, मेहसाणा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद, उन्होंने विभिन्न स्थानों से साक्ष्य एकत्र किए जहां दोनों आरोपियों ने घटना की तारीख के बाद अपनी गिरफ्तारी तक एक साथ दिन बिताए थे। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर, विचारण न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और आरोप तय किए। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध किया।

4. विचारण न्यायालय ने विचारण के लिए निम्नलिखित आरोप विरचित किए:

"(1) 12-12-1994 को शाम करीब छह बजे से पहले आप दोनों ने एक फरार आरोपी, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, अर्थात् पीयूष सेवंतीलाल रावल के साथ मिलकर अहमदाबाद में नवरंगपुरा क्षेत्र में स्थित शकुंतल अपार्टमेंट, सीएन विद्यालय के सामने हाउस नंबर 1 में मृतक महेंद्रभाई की हत्या करने की आपराधिक साजिश रची और ऐसा करके आपने इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) के तहत अपराध किया है।

(2) इसके अलावा, उपरोक्त तिथि, समय और उपरोक्त स्थान पर अपने आपराधिक षडयंत्र को पूरा करने के संबंध में, आरोपी नंबर 1 और फरार आरोपी पीयूष ने मृतक महेंद्रभाई गड्डा के शरीर पर चाकू से कई वार किए, जिससे उन्हे गंभीर चोटें आईं और जानबूझकर हत्या करने के इरादे से चोटें पहुंचाकर आपने उसकी हत्या कर दी और ऐसा करके आप आरोपियों ने इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 120 (बी) के तहत अपराध किया है।

(3) इसके अलावा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर, आपके उपरोक्त आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में, हत्या के अपराध में कारावास की सजा से बचने के इरादे से मृतक के शव को स्थानांतरित करके और अपराध स्थल की सफाई करके सबूतों को नष्ट कर दिया और इस प्रकार आप आरोपियों ने इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

(4) इसके अलावा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर, अपने आपराधिक षड्यंत्र के अनुसार, शव के टुकड़े करने के लिए, सुई, जूट-धागा, प्लास्टिक की थैली, लोहे की ब्लेड आदि इकट्ठा करके साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया, यह देखने के लिए कि शव की पहचान के साथ-साथ महेंद्रभाई गड्डा को लगी चोटों के बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं हो, आपने सबूत मिटाने का प्रयास किया और ऐसा करके आपने इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 511 सपठित धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

(5) इसके अलावा, उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर, आप आरोपी नंबर 1 ने चाकू जैसा घातक हथियार अपने पास रखकर पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद शहर द्वारा प्रकाशित शस्त्र निषेध की सार्वजनिक सूचना का उल्लंघन किया है और ऐसा करके आपने इस

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत दंडनीय अपराध किया है।"

5. विचारण न्यायालय, पूर्ण सुनवाई के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ए1 ने आईपीसी की धारा 302 और 201 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय अपराध किया है और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, अदम अदायगी 3 महीने का कठोर कारावास, और आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे दो साल के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, अदम अदायगी तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। यहां अपीलकर्ता, जिसे केवल आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया, अदम अदायगी 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

6. दोनों अभियुक्तों ने विचारण न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर अलग-अलग आपराधिक अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता के संबंध में सजा बढ़ाने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की। उच्च न्यायालय ने आरोपियों द्वारा की गई अपीलों को खारिज करते हुए, आपराधिक विविध आवेदन में एक आदेश पारित किया, जिसमें आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को बढ़ाकर सात वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया और 7,000/- रुपये का जुर्माना लगाया, अदम अदायगी उसे दो साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास

भुगतना होगा। उसी निर्णय को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष है।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता के खिलाफ सबूतों का मूल्यांकन करने में गंभीर त्रुटि की है और उसके बयानों के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की अनदेखी करते हुए उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया है। अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 कभी भी अपराध का हिस्सा नहीं थी और जब आरोपी नंबर 1 ने उसके घर में प्रवेश किया और उसके पति की बेरहमी से हत्या करने का जघन्य अपराध किया तो उसके चुप रहने के पीछे का कारण यह था कि वास्तव में, घटना के समय दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलकर्ता अपने बच्चों के साथ सो रही थी। आरोपी नंबर 1 ने उसे बहुत डराया कि अगर उसने शोर मचाया तो उसके द्वारा उसके बच्चों पर भी हमला किया जा सकता है, जिससे वह घटना का मूक दर्शक बनी रही।

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि घटना के बाद, अपीलकर्ता जानबूझकर आरोपी नंबर 1 के साथ नहीं भागी, बल्कि उनके रिश्ते का फायदा उठाकर, आरोपी नंबर 1 उसे जबरदस्ती विभिन्न स्थानों पर ले गया और उसे फर्जी नामों के तहत रखा। यह बताना भी उपयुक्त होगा कि अपीलकर्ता घटना के बाद आरोपी नंबर 1 के साथ रहने के दौरान चुप रही क्योंकि उसे डर था कि मुख्य आरोपी के साथ उसके अवैध संबंध के कारण पुलिस और परिवार के सदस्य सबसे पहले उसे ही दोषी मानेंगे। यहां तक कि उस अवधि के दौरान जब अपीलकर्ता को आरोपी नंबर 1 द्वारा उनकी गिरफ्तारी तक विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया था, वह किसी की मदद नहीं ले सकी क्योंकि जब भी मुख्य आरोपी कमरे से बाहर जाता था, तो वह अपीलकर्ता को अंदर बंद कर देता था। यह तथ्य पीडब्लू 19 (इएक्सटी 72) के बयान से स्पष्ट है। उस समय

उसका व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक था और उसने सबूतों को नष्ट करने में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन निचली अदालतों ने आईपीसी की धारा 201 के तहत उसे दोषी ठहराने से पहले सही कानूनी परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन नहीं किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने निचली अदालतों के आदेश पर कटाक्ष करते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार से केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य अर्थात उसके घर से मिले सुई, जूट के धागे, प्लास्टिक की थैली, लोहे के ब्लेड आदि को अपराध से जोड़ने के आधार पर अपराध के लिए और मुख्य अपराधी की सहायता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

9. एक और प्रबल तर्क प्रस्तुत करते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले में कानूनी सिद्धांतों को लागू किए बिना यांत्रिक तरीके से आक्षेपित आदेश पारित किया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दिखाने के लिए हमारा ध्यान ईएक्सटी 4 की ओर आकर्षित किया कि अपीलकर्ता पर वास्तव में आईपीसी की धारा 511 सपठित धारा 201 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उस स्थिति में, यदि अपीलकर्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे अधिकतम सजा दी जाएगी जो केवल तीन साल और छह महीने तक होती है। आनंद दगडु जाधव और अन्य बनाम रुक्मिणीबाई आनंद जाधव और अन्य (1993) पूरक (3) एससीसी 68 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुरजोर प्रयास किया कि विचारण न्यायालय ने ठोस कानूनी सिद्धांत द्वारा इस पहलू पर विचार करने के बाद सही दृष्टिकोण अपनाया और तदनुसार सजा दी। भले ही यह न्यायालय अपीलकर्ता को अपराध का दोषी पाता है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल करते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए।

10. हालाँकि, गुजरात राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने कानून के उचित सिद्धांतों का पालन करते हुए और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की सत्यता को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय दिया है, सज़ा को उचित रूप से बढ़ाया गया है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर ध्यान देने के बाद, निम्नलिखित मुद्दे इस न्यायालय के विचारार्थ आते हैं:

1) क्या निचली अदालतें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में सही थीं?

2) क्या उच्च न्यायालय का स्वत: संज्ञान लेकर सजा को दो साल से बढ़ाकर सात साल करने का फैसला सही था?

12. मैंने मामले से जुड़े कई पहलुओं पर विचार किया है। अभियोजन का पूरा मामला अमी, जो मृतक और अपीलकर्ता की बेटी है, के प्रत्यक्ष साक्ष्य को छोड़कर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य मजबूत, ठोस और अकाट्य होने चाहिए, जिससे केवल यही निष्कर्ष निकले कि अपराध केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और इससे कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले के तथ्यों पर गहन नजर डालने से पता चलता है कि आरोपी नंबर 1 और 2 के बीच अवैध संबंध थे और उसी

उद्देश्य के लिए उन्होंने मृतक की हत्या की है और शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता का भाई और मृतक का साला है।

14. अभियोजन पक्ष ने, अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, बड़े पैमाने पर दस्तावेजी सबूतों के अलावा 48 गवाहों की जांच की है। पूरी सुनवाई के बाद विचारण न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि आरोपी नंबर 1 ने फरार आरोपी की मदद से मृतक की हत्या की और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। जहां तक आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता का सवाल है, न्यायालय ने कहा है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि इसमे उसकी सहमति थी या मृतक की हत्या करने के लिए आरोपी नंबर 1 के साथ वह मिली हुई थी और इस तरह आरोपी नंबर 2 हत्या के अपराध के लिए और आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए कृत्यों के लिए दोषी नहीं है। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि उसकी चुप्पी डर और असहाय स्थिति में होने और इस आशंका के कारण है कि उसके बच्चों और खुद को आरोपी संख्या 1 और फरार आरोपी द्वारा घायल किया जा सकता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आरोपी नंबर 2 मदद नहीं मांग सकती थी। लेकिन विचारण न्यायालय की राय थी कि दोपहर 1.00 या 2.00 बजे तक आरोपी नंबर 1 अपराध की जगह से दूर था और उस दौरान उसे मदद मिल सकती थी।

15. विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि उसके बाद के आचरण को उसकी सहमति या हत्या के सबूत को नष्ट करने के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अपराध स्थल पर पाए गए काटने के उपकरण, ब्लेड, प्लास्टिक पीले रंग के टैग और अन्य सामान और आरोपी नंबर 1 के रिश्तेदार के घर से पाए गए प्लास्टिक पीले टैग का दूसरा भाग यह साबित करेगा कि आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 द्वारा चुप रहकर हत्या के सबूत मिटाने की तैयारी की गई थी। फिर भी न्यायालय को

लगा कि वह साजिशकर्ता नहीं है लेकिन 12-12-1994 को सुबह 7.30 बजे के बाद उसने आरोपी नंबर 2 को फिर से अपने घर में घुसने और बेडरूम के बाथरूम में शव के साथ रहने की इजाजत दे दी। उस कृत्य से पता चलता है कि या तो डर के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से, उसने आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध को बढ़ावा दिया या सहायता की। अपराध के सबूतों को गायब करने के संबंध में, विचारण न्यायालय द्वारा आगे यह देखा गया कि हालांकि हत्या के अपराध के सबूतों को गायब करने में आरोपी नंबर 2 की भागीदारी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चुप रहकर उसने हत्या के सबूतों को गायब करके इस अपराध को बढ़ावा दिया और इस प्रकार दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

16. उच्च न्यायालय ने अपीलों के साथ-साथ सजा में स्वतः संज्ञान लेकर वृद्धि के लिए विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से देखा है कि आरोपी नंबर 1 ने ए2 की सहमति से मृतक के घर में प्रवेश किया होगा। इसके अलावा, उसने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को सभी झूठे जवाब दिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब 6 से 7 घंटे तक आरोपी नंबर 1 घर में मौजूद नहीं था, कम से कम तब उसे घटना के बारे में किसी को सूचित करना चाहिए था। ये सभी स्पष्ट रूप से उसे आरोपी नंबर 1 के साथ अपराध में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। सबूत यह भी साबित करते हैं कि आरोपी नंबर 2 ने आरोपी नंबर 1 को घर में प्रवेश करने की अनुमति दी और उसे अन्य सामान रखने की अनुमति दी। उपरोक्त सभी कृत्य अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं जो दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साजिश रची की गई है, लेकिन चूंकि राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने अंततः माना कि ठोस, विश्वसनीय और सुसंगत सबूतों के माध्यम से, अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि आरोपी नंबर 2, हालांकि यह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पति की आरोपी नंबर 1 द्वारा

बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसने किसी को सूचित नहीं किया और न ही शिकायत दर्ज की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को दोषी ठहराना उचित था। लेकिन विचारण न्यायालय ने कम सज़ा दी जो अनुचित है, न्याय का उल्लंघन है और परिणामस्वरूप, सज़ा को बढ़ाकर सात साल कर दिया गया।

17. इस समय, मैं बेहतर मूल्यांकन के लिए आईपीसी की धारा 201 को उद्धृत करना उचित समझता हूं।

> 201. अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना- जो कोई भी, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि एक अपराध किया गया है, अपराधी को कानूनी सज़ा से बचाने के इरादे से, उस अपराध के घटित होने के किसी भी सबूत को गायब कर देता है, या उस इरादे से उस अपराध के संबंध में कोई झूठी जानकारी देता है; यदि कोई मृत्युदंड अपराध- यदि वह अपराध जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि किया गया है, मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उसे किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है; यदि आजीवन कारावास से दंडनीय है- और यदि अपराध 1 [आजीवन कारावास], या कारावास से दंडनीय है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा; यदि दस वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है- और यदि अपराध किसी भी अवधि के

कारावास से दंडनीय है जो दस वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, अपराध के लिए प्रावधान किए गए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि अपराध के लिए प्रावधान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण ए, यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या कर दी है, बी को सजा से बचाने के इरादे से शव को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए को सात साल की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।

18. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सौ. विजया उर्फ बेबी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 8 एससीसी 296 में निर्धारित किया गया है, आईपीसी की धारा 201 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, निम्नलिखित घटक आवश्यक हैं-

क. कि कोई अपराध किया गया है;

ख. कि अभियुक्त ऐसे अपराध के घटित होने के बारे में जानता था या उस पर विश्वास करने का उसके पास कारण था;

ग. कि ऐसी जानकारी या विश्वास के साथ उसने-

1. उस अपराध के घटित होने के किसी भी सबूत को गायब कर दिया; या

2. उस अपराध के संबंध में कोई भी ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में वह जानता था या मानता था कि वह झूठ है;

घ. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसने अपराधी को कानूनी सज़ा से बचाने के इरादे से ऐसा किया।

.... इसलिए, सहायक कार्योत्तर कानून बनाने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि अभियुक्त को किए गए अपराध के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उसे स्वीकार करना चाहिए, राहत देनी चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए या उसकी सहायता करनी चाहिए और आम तौर पर किसी अपराधी को उसकी गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने या सजा भुगतने में बाधा डालने के लिए जो भी सहायता दी जाती है, वह सहायता करने वाले को एक सहायक बना देती है। आईपीसी की धारा 201 के अनुसार यह आवश्यक है कि आरोपी का इरादा अपराधी को बचाने का रहा हो। इसे अलग ढंग से कहें तो, अपराधी को बचाने का इरादा, आरोपी का प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यह तथ्य कि, छिपाने से उस प्रभाव की संभावना होगी, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धारा 201 केवल संभावना के बजाय इरादे की बात करती है।"

19. आपराधिक मुक़दमा कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप पर विचार करते समय, अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी ने सबूतों को गायब करने और और अपराधी को बचाने के इरादे से मामले में सक्रिय रूप से भाग लिया। आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए, यह आवश्यक है कि आरोपी के अपराध को इंगित करने वाले सभी तत्व साबित हों और केवल संदेह पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को कभी भी संभावनाओं के आधार पर या धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उपरोक्त के आलोक में, यह जांच की जानी

चाहिए कि क्या अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

20. अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा पर सवाल उठा रही है, जिसकी एक तरफ उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी और दूसरी तरफ, वह उच्च न्यायालय द्वारा सजा को 2 साल से बढ़ाकर 7 साल करने के आदेश से व्यथित है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और विशेष रूप से अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 को दोषी ठहराने के लिए कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क को पढ़ने के बाद, स्वीकृत तौर पर आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302, 120 (बी) और 201 के साथ आईपीसी की धारा 511 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए। विचारण न्यायालय ने आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता को अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है। यहां, मामले में शामिल मुद्दों के बेहतर मूल्यांकन के लिए, मैं विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के प्रासंगिक हिस्से को उद्धृत करना चाहूंगा, जो इस प्रकार है:

> "मैं मृतक की हत्या के लिए आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए कृत्य के लिए आरोपी नंबर 2 को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने में असमर्थ हूं। यह सच है कि उसकी चुप्पी डर के कारण हो सकती है और कोई भी उस डर को समझ सकता है जो उस महिला के मन में होता है जिसने अपने पति पर चाकुओं से हमला होते हुए असहाय हालत में देखा था और उसके मन में खुद को और अपने बच्चों को आगे के हमले से बचाने की चिंता थी......इसी प्रकार, मैं इस तथ्य से भी अवगत हूं कि आरोपी नंबर 2 की ओर से यह चुप्पी इस ओर भी

इशारा कर सकती है कि आरोपी नंबर 2 भी साजिशकर्ताओं में से एक है.....

......उसने तलाक लेने की इच्छा जाहिर की थी। इसलिए, उसका किसी भी प्रकार से अपने पति की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, ये दो परिस्थितियाँ मुझे आरोपी नंबर 2 को मृतक की हत्या की साजिश के साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में नहीं मानने के लिए प्रेरित करती हैं।

.... आरोपी का बाद का आचरण उसके अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है। आरोपी नंबर 2 को उनके द्वारा किए गए अपराध के सबूतों को गायब करने के अपराध में दोषी ठहराया जा सकता है।

.. उपरोक्त चर्चा किए गए सबूतों से, मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है कि आरोपी नंबर 1 ने फरार आरोपियों की मदद से मृतक को कई चोटें पहुंचाकर हत्या की थी। मेरा मानना है कि आरोपी नंबर 2 को मृतक की हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। अपराध के साक्ष्यों को गायब करने के संबंध में, हालांकि हत्या के अपराध के उक्त सबूतों को गायब करने में आरोपी नंबर 2 की भागीदारी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चुप्पी साध कर उसने अप्रत्यक्ष रूप से हत्या के सबूतों को गायब करने के अपराध को बढ़ावा दिया है। मैं उक्त बिन्दु का उत्तर देता हूं कि आरोपी संख्या 1 हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और आरोपी नंबर 2 को हत्या के उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता है। मैं बिंदु संख्या 4 का उत्तर देता हूं कि दोनों

आरोपियों को आईपीसी की धारा 201 के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।"

21. विचारण न्यायालय के संपूर्ण निष्कर्षों को देखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायालय ने अपीलकर्ता को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी है कि वह किसी भी तरह से अपराध में शामिल नहीं है। फैसले के पैरा 73 में, विचारण न्यायालय द्वारा एक बार में स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया था कि हत्या के अपराध के उक्त सबूत को गायब करने में आरोपी नंबर 2 की भागीदारी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चुप रहकर, उसने परोक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर विचारण न्यायालय ने पाया कि या तो डर के कारण या उसे ज्ञात किसी कारण से, वह चुप रही और आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध को बढ़ावा दिया या सहायता की।

22. स्वीकृत तौर पर एकमात्र चश्मदीद गवाह अमी के साक्ष्य को छोड़कर अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। चश्मदीद गवाह ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता रो रही थी और वह आरोपी नंबर 1 से अपने पति को न मारने की गुहार लगा रही थी। उसने जिरह में आगे कहा कि आरोपी नंबर 1 ने उसकी मां/अपीलकर्ता को चुप रहने और कोई परेशानी न करने के लिए कहा क्योंकि आरोपी नंबर 1 और फरार आरोपी वापस आ जाएंगे। आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में भी यही बात दोहराई।

23. प्रत्यक्षदर्शी अमी के साक्ष्य का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

"मैं खाट से मम्मी की तरफ कूदी। मैं उठते ही वहां गई। मेरी मम्मी तुरंत मुझे ड्राइंग रूम में ले गईं। यह सच नहीं है कि मेरी मां वहां

पूज़ा के साथ चुपचाप खड़ी थीं, वह कह रही थीं "मत मारो। मत मारो"

"अगले दिन सुबह जब मैं सुबह 7:30 बजे उठी, तो किशोरभाई और एक अन्य व्यक्ति बेडरूम से बाहर आए और किशोरभाई ने मुझे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनके इशारे को अस्वीकार कर दिया। उस समय, उनके साथ वाले व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। किशोरभाई ने मेरी मम्मी से कहा कि वे चुप रहें और कोई परेशानी न करें क्योंकि वे वापस आ रहे हैं।"

24. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता के बयान का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"यह सच है। जाते समय किशोर ने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारे घर में लाश पड़ी है, हम जा रहे हैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, इसलिए जब तक हम वापस न आएं तब तक चुप रहना, कुछ मत करना।"

25. मैं निचली अदालतों के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि चुप रहकर, आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से हत्या के सबूतों को गायब करने के अपराध को बढ़ावा दिया है। चुप रहना और आरोपी नंबर 1 के साथ फरार रहना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सबूतों की आपूर्ति नहीं करेगा या उस अंतर को नहीं भरेगा जो आईपीसी की धारा 201 के तहत साक्ष्यों को साबित करने के लिए आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने, विशेष रूप से यह देखते हुए कि आरोपी नंबर 2 का सबूतों के गायब होने से कोई लेना-देना नहीं है और मकसद के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना, उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया है। वास्तव

में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय मकसद के संबंध में कोई तर्क नहीं दे सका जो कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध को साबित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। चुप रहने के तथ्य के संबंध में चश्मदीद गवाह के साक्ष्य और अपीलकर्ता के 313 बयान से पता चलता है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

26. राघव प्रपन्न त्रिपाठी बनाम यूपी राज्य, एआईआर 1963 एससी 74 मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 201 और आईपीसी की धारा 201 के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक घटकों पर विचार किया है। उसी का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "इस प्रकार इन दोनों अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और उनकी अपील खारिज कर दी गई है। रामानुज दास और जय देवी के मामले के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि कमला और उनके बेटे मधुसुदन के शव रामानुज दास के घर में नहीं मिले थे और इसलिए, हो सकता है कि उन्हें हटा दिया गया होगा; कि कमरों के अंदर और बाहर छत पर भी खून के धब्बे धोने की कोशिश की गई थी; कि रामानुज दास और जय देवी की जानकारी और सक्रिय सहयोग के बिना शवों को नहीं हटाया जा सकता था और इसके अलावा रामानुज दास और जय देवी दोनों फरार हो गए। इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा इन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को उचित ठहराया गया। यह सच है कि हत्या रामानुज दास के घर में की गई थी और यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि लिविंग रूम के अंदर और बाहर खून धोया गया था और इसके हर निशान को मिटाने का

असफल प्रयास किया गया था। यह भी हो सकता है कि रामानुज दास और जय देवी दोनों को शवों को हटाने की जानकारी हो लेकिन धारा 201 के लिए आवश्यक है कि अपराध के घटित होने के किसी भी सबूत को गायब कर दिया जाए या अपराध के संबंध में कोई ऐसी जानकारी दी जाए जिसके बारे में कोई व्यक्ति जानता हो या झूठ मानता हो। इस मामले में दोनों का कोई सबूत नहीं है। यह नहीं दिखाया गया है कि इन दोनों अपीलकर्ताओं ने कोई सबूत गायब किया हो। यह बहुत प्रबल संदेह हो सकता है कि यदि घर से शव निकाले गए या खून धोया गया, तो अपीलकर्ता व्यक्ति का इसमें हाथ रहा होगा, लेकिन फिर भी यह संदेह बना हुआ है, यहाँ तक कि यह एक मजबूत संदेह भी है। यह सच है कि वे फरार थे लेकिन केवल फरार होने से वह कमी पूरी नहीं होगी या वह सबूत नहीं मिलेगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 201 महतावपूर्ण घटकों को साबित करने के लिए आवश्यक है। हमारी राय में रामानुज दास और जय देवी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। इसलिए वहां अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें स्वतंत्र किया जाना चाहिए।"

27. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों की आपराधिक मनःस्थिति के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाले बिना अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में गलती की, जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में तय किया है। विशेष रूप से, जब विचारण न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो उसे मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जब अपीलकर्ता और आरोपी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण

न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, तो उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपीलकर्ता की सजा बढ़ाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के तहत उसे नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने आरोपी की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए सजा को 7 साल तक बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क नीचे दिया गया है:

> "साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी ने सार्वजनिक परिवहन यानी एएमटीसी बस से यात्रा की। इसलिए, घर में लगभग 6-7 घंटे तक आरोपी नंबर 1 की अनुपस्थिति में, कम से कम वह किसी को सूचित कर सकती थी। इसके अलावा, जब वह विभिन्न स्थानों पर घूम रही थी, तो उसके पास पर्याप्त अवसर थे। हालाँकि, उसने इनमें से किसी भी अवसर का उपयोग नहीं किया। इन सभी में स्पष्ट रूप से वह आरोपी नंबर 1 के साथ अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है।"
>
> .... उसके बाद भी, वह चुप रही, आरोपी नंबर 1 के साथ चली गई, पति-पत्नी के रूप में फर्जी नामों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर रही और डेढ़ महीने की अवधि के लिए फरार रही। उपरोक्त से, अभियोजन पक्ष द्वारा साजिश का संकेत देने वाले अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी साबित की गई है। निचली अदालत ने इस पर विचार किया लेकिन साजिश के सिद्धांत पर अविश्वास किया। भले ही हम निचली अदालत द्वारा दिए गए उक्त तर्कों से संतुष्ट नहीं हैं, हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्य द्वारा उस संबंध में कोई अपील दायर नहीं की गई है।"

....यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी नंबर 2 को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया था और केवल धारा 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था। जैसा कि पहले कहा गया है, चूंकि राज्य ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है, इसलिए हम उक्त पहलू से निपटने की स्थिति में नहीं हैं।

.... हालाँकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पति की मूल आरोपी नंबर 1 ने बेरहमी से हत्या कर दी है, लेकिन उसने किसी को सूचित नहीं किया और न ही शिकायत दर्ज की। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी नंबर 2 को आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराना उचित था और उसकी सजा को बरकरार रखा गया है।

.... यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय ने न केवल धारा 201 के उद्देश्य को नजरअंदाज करते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का अनुचित मूल्यांकन किया है, बल्कि मामले के चौंकाने वाले तथ्य, जिसके कारण आरोपी नंबर 1 द्वारा मृतक की हत्या हुई और आरोपी नंबर 2 द्वारा धारा 201 के तहत किए गए अपराध को भी नज़रअंदाज़ किया और वह सज़ा दी जो अनुचित है और न्याय का दुरुपयोग है। विचारण न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि धारा 201 आईपीसी की धारा 302 के साथ जुड़ी हुई है और उसी के अनुसार सजा देनी चाहिए थी।"

28. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि सजा का अपराध के अनुरूप होना सजा नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। सज़ा पर्याप्त रूप से उचित होनी चाहिए, दोषी की प्रकृति के अनुपात में होना एक महत्वपूर्ण कारक है। सज़ा देना विचारण न्यायालय के विवेक का मामला है और सामान्य परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय इस तरह के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वह तभी हस्तक्षेप करेगा जब उसे पता चलेगा कि न्याय का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और जहां सजा सुनाने वाले न्यायालय द्वारा विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय को दोषसिद्धि की अपील से उस मामले के गुण-दोष के आधार पर निपटाना होगा और एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि करके सही निर्णय लिया था, तो उसे इस पहलू पर गौर करना होगा कि सजा आनुपातिक थी या नहीं। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से कि अपीलकर्ता हत्या करने में सक्रिय रूप से शामिल है और साजिश के संबंध में निष्कर्ष और विशेष रूप से, यह देखते हुए कि चूंकि राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है, इसलिए वह इससे निपटने की स्थिति में नहीं है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से सजा बढ़ा दी है। उच्च न्यायालय के संपूर्ण तर्क को देखते हुए, मुझे लगता है कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की गई थी और वास्तव में उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था, लेकिन यह केवल सजा के पहलू से भिन्न था। सजा बढ़ाने और अपील खारिज करने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क आईपीसी की धारा 302 या 120 बी के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए तब एक वैध और सही तर्क हो सकता है, जब राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दाखिल की हो। लेकिन ऐसे तर्क के आधार पर अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध को

साबित करने वाले घटक पूरी तरह से अलग हैं। उसकी केवल चुप्पी से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसने अपराध किया है। मौजूदा मामले में विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ही मामले को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहे, उन्होंने धारणाओं पर अधिक भरोसा किया और धारणाओं के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया, जो स्थापित कानून के विपरीत है।

29. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं दोनों मुद्दों को आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी राज्य के खिलाफ मानता हूं।

30. सामान्यतः, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में, जहां दोनों निचली अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए थे, यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन, यह एक ऐसा मामला है जहां दोनों निचली अदालतों ने आईपीसी की धारा 201 घटकों को संतुष्ट किए बिना, अनुमानों और कल्पनाओं पर आरोपी संख्या 2/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है, इसलिए इस न्यायालय को इसमे हस्तक्षेप करना पड़ा है।

31. चल रही चर्चा पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि अभियोजन आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता/अभियुक्त संख्या 2 के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है। इस न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा पहले ही भुगत चुकी है। मैं आपराधिक अपील संख्या 833/1997 और आपराधिक अपील संख्या 833/1997 में आपराधिक विविध अपील संख्या 1121/1998 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करता हूँ और तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

प्रफुल्ल सी पंत, जे 1. मुझे माननीय श्री न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना द्वारा ड्राफ्ट किए गए फैसले को पढ़ने का लाभ मिला है, जिसमें उन्होंने माना है कि अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप साबित नहीं हुआ है और उसके खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि रद्द किए जाने योग्य है। बड़े सम्मान के साथ, मैं विनम्रतापूर्वक नीचे दिए गए कारणों से उक्त दृष्टिकोण से असहमत हूं:-

2. संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 1981 में महेंद्रभाई (मृतक) से शादी की और इस विवाह से दो बेटियां पैदा हुईं। परिवार अहमदाबाद के शकुंतल अपार्टमेंट में रहता था। मृतक एक चितरंजन सोसायटी, नारणपुरा में और दूसरा शकुंतल अपार्टमेंट में हेल्थ क्लब चला रहा था। पीडब्लू-3 प्रदीप कामदार (शिकायतकर्ता) अपीलकर्ता का भाई है। शकुंतल अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले अपीलकर्ता अपने परिवार के साथ शिकायतकर्ता के साथ रहती थी। किशोर ठक्कर (ए-1) मृतक द्वारा संचालित हेल्थ क्लब में कर्मचारी था। उसने अपीलकर्ता के साथ अवैध संबंध विकसित किए। जब अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह मृतक के साथ अपने संबंध तोड़ना चाहती है, तो शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने उसे ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी क्योंकि इस विवाह से उसके दो बच्चे थे। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि किशोरभाई (ए-1) भी उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। इसके बाद, जब शिकायतकर्ता ने महेंद्रभाई को अपने घर में ए-1 को अनुमति नहीं देने की सलाह दी, तो उन्होंने ए-1 को नौकरी से निकाल दिया। 11.12.1994 को, अपीलकर्ता अपने पति (मृतक) और बच्चों के साथ दोपहर के भोजन के लिए शिकायतकर्ता के घर आई और लगभग 2.30 बजे वापस लौट आई। बेटियों की उम्र आठ साल और चार साल थी। दोनों परिवार नियमित रूप से फोन पर संपर्क में रहते थे। 12.12.1994 की सुबह, शिकायतकर्ता की पत्नी ने अपीलकर्ता की छोटी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में

पूछताछ करने की कोशिश की। लेकिन फोन लगातार व्यस्त था। सुबह लगभग 11.30 बजे जब उसने अपीलकर्ता को फोन किया और उसके पति (मृतक) के बारे में पूछा, तो उसने (अपीलकर्ता ने) उसे बताया कि वह नारणपुरा हेल्थ क्लब गया है। इसके बाद, शिकायतकर्ता (पीडब्लू-3) ने दोपहर 3 बजे फोन किया। अपीलकर्ता ने बताया कि महेंद्रभाई (मृतक) बंबई गए है। इससे शिकायतकर्ता को संदेह हुआ क्योंकि महेंद्रभाई जब भी अहमदाबाद से बाहर जाते थे, तो उन्हें सूचित करते थे। शाम लगभग 4.00 बजे, शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन (अपीलकर्ता) के घर आया और दरवाजे की घंटी बजाई। वे घर में घुसे तो देखा कि छोटी बेटी पूजा बुखार में डाइनिंग टेबल के पास पड़ी हुई है। जब शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता से महेंद्रभाई के बॉम्बे जाने का कारण पूछा, तो अपीलकर्ता ने स्पष्टीकरण दिया कि महेंद्रभाई ने उसे अपनी बॉम्बे यात्रा का खुलासा न करने के लिए कहा था। चूंकि शाम के 4:00 बज रहे थे और अपीलकर्ता की बड़ी बेटी अमी (पीडब्लू-34) को स्कूल से वापस लाया जाना था, पीडब्लू-3 ने अपीलकर्ता को जाकर बच्ची को लाने के लिए कहा। इस बीच, पीडब्लू-3 ने पाया कि अपीलकर्ता का स्नान कक्ष अंदर से बंद था। अचानक स्नान कक्ष का दरवाजा अंदर से खुला और किशोर (ए-1), जिसका अपीलकर्ता के साथ अवैध संबंध था, बाहर आया और भागने की कोशिश की। उसकी शर्ट के बटन नहीं लगे थे. जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसकी शर्ट नीचे गिर गई और उसने केवल पैंट पहन रखी थी और वह भाग गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने बाथरूम के अंदर प्रवेश किया और देखा कि महेंद्र भाई का शव खून से लथपथ था। अपीलकर्ता, जिसे अमी (पीडब्लू-34) को लाने के लिए भेजा गया था, वापस नहीं आई। ऐसे में, शिकायतकर्ता अपनी पत्नी को अपीलकर्ता के घर छोड़कर स्कूल गया और अमी को लेकर आया।

3. इसके बाद, शिकायतकर्ता एलिसब्रिज पुलिस स्टेशन, फिर नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श 22) दी, जिसे आईसीआर संख्या

759/1994 के रूप में पंजीकृत किया गया। पुलिस अपीलकर्ता के घर आई, शव को अपने कब्जे में लिया, जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीडब्लू-1 डॉ. दिलीप मनुभाई देसाई ने पोस्टमार्टम किया और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 17/18) तैयार की। जांच पूरी होने पर, किशोरभाई (ए-1) और अपीलकर्ता (ए-2) के खिलाफ धारा 302, 120बी और 201 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण न्यायालय ने ए-1 को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, अपीलकर्ता (ए-2) को आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन धारा 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। ए-1 को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी गई, और ए-1 और ए-2 में से प्रत्येक को दो साल के कठोर कारावास और 5000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी गई, अदम अदायगी आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

4. दोनों दोषियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें (ए-1 द्वारा आपराधिक अपील संख्या 831/1997 और ए-2 द्वारा आपराधिक अपील संख्या 833/1997) दायर कीं। उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में केवल ए-2 के विरुद्ध सजा बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में ए-2 को बरी करने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। पक्षों को सुनने के बाद, ए-1 के साथ-साथ ए-2 की अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं, और ए-2 की सजा को बढ़ाकर सात साल के कठोर कारावास और 7,000/- रुपये का जुर्माना कर दिया गया, अदम अदायगी दो साल के लिए कठोर कारावास

भुगतने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.10.2006 से व्यथित होकर, ए-2 इस अपील में हमारे समक्ष है।

5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलें माननीय श्री न्यायमूर्ति एनवी रमना के फैसले में पहले ही उल्लिखित हैं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

6. रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कुल मिलाकर 48 गवाह का अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया है।

7. पीडब्लू-1 डॉ. दिलीप मनुभाई देसाई, जिन्होंने 13.12.1994 को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया, ने मृतक (महेंद्रभाई) की हत्या को साबित किया है। उन्होंने बयान दिया है कि मृत शरीर पर पचास बाहरी चोटें थीं, जिनमें से बाहरी चोटें संख्या 13, 14, 16, 18, 20, 21, 28 और 30 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने आगे बताया कि चोटें संभवतः चाकू से लगी हैं। उनके द्वारा बताई गई मौत का कारण मृतक को लगी चाकू की चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 17/18 को प्रमाणित किया है।

8. पीडब्लू-3 प्रदीप कामदार (शिकायतकर्ता), जो अपीलकर्ता का भाई है, ने पूरी अभियोजन कहानी सुनाई है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। संक्षिप्तता के लिए, इसे दोहराया नहीं जा रहा है।

9. पीडब्लू-34 अमी अपीलकर्ता की बड़ी (नाबालिग) बेटी है। उसने कहा है कि उनके पिता नारणपुरा और शकुंतल अपार्टमेंट में हेल्थ क्लब चलाते थे। किशोर (ए-1) हेल्थ क्लब में काम करता था, जिसे दिवाली से पहले नौकरी से हटा दिया गया था। उसने आगे बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात (11 और 12 दिसंबर, 1994) को जब बिस्तर को धक्का दिया गया तो उनकी नींद खुल गई। उसने देखा कि दो व्यक्ति किशोर और

एक दुबला व्यक्ति उसके पिता को पीट रहे थे। (उक्त दुबला व्यक्ति अभी भी फरार बताया गया है) उसने आगे बताया कि उसकी मां पूजा (अपीलकर्ता की छोटी बेटी) के साथ दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने आगे बताया कि जब वह रोने लगीं तो उसकी मां उन्हें ड्राइंग रूम में ले गईं। उसने आगे बताया कि उसके बाद उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ और जब सुबह वह उठी तो उसने किशोर (ए-1) और उसके साथी को कमरे से बाहर निकलते देखा। उसने आगे बताया कि अगली सुबह उसकी मां ने उसे दूसरे कमरे से जुड़े बाथरूम में नहाने के लिए कहा। उसने बताया कि वह वंदना स्कूल में पढ़ती थी। उसने जिरह में इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि उसके मामा (शिकायतकर्ता) उसे स्कूल में लेने आए थे।

10. पीडब्लू-3 प्रदीप कामदार के बयान की पुष्टि न केवल पीडब्लू-34 अमी के बयान से होती है, बल्कि पीडब्लू-23 मीनाबेन दीपकभाई देसाई के बयान से भी होती है। इस गवाह ने कहा है कि 12.12.1994 को जब वह अपने बेटे को वंदना स्कूल से अपने घर ला रही थी, तो उसकी मुलाकात अपीलकर्ता से वंदना स्कूल के पास हुई। उसने यह भी देखा कि किशोर (ए-1) एक ऑटोरिक्शा में आया। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था और वह सिर्फ पैंट में था। उसने उससे (पीडब्लू-23) पद्मिनी (अपीलकर्ता) को बुलाने के लिए कहा। उसने उसे (पद्मिनी को) बुलाया और पद्मिनी किशोर (ए-1) के साथ ऑटोरिक्शा में चली गई।

11. पीडब्लू-7 योगेश पन्नालाल ने बताया कि 12.12.1994 को शाम 4.00 से 5.00 बजे के बीच एक आदमी नंगे पैर, जिसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था, एक महिला के साथ उसकी दुकान में आया। उन्होंने एक टीशर्ट मांगी और एक जर्सी खरीदी। महिला ने इसके लिए भुगतान किया। इस गवाह ने ए-1 की पहचान उस

आदमी के रूप में की है जो नंगे पैर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर बिना कपड़ों के आया था और ए-2 की पहचान उस महिला के रूप में की है जिसने पैसे दिए थे।

12. पीडब्लू-6 नवाजबहमद रफीउद्दीन शेख ने यह बयान देकर कहानी को और पुष्ट किया कि वह एक जूते की दुकान चलाता था और 12/12/1994 को शाम लगभग 6.00 बजे एक व्यक्ति नंगे पैर एक महिला के साथ उसकी दुकान पर आया और 45 रुपये में चप्पल खरीदी और महिला ने पैसे चुकाये।

13. घटना के बाद ए-1 और ए-2 कैसे फरार हो गए और एक साथ रहने लगे, यह भी पीडब्ल्यू-19, पीडब्ल्यू-28, पीडब्ल्यू-32, पीडब्ल्यू-39 और पीडब्ल्यू-40 की गवाही में रिकॉर्ड में आ गया है। पीडब्लू-19 कनुभाई सोमाभाई वलंद ने कहा है कि वह नाईसमाज धर्मशाला के प्रबंधक हैं और उन्होंने बताया कि ए-1 और ए-2 धर्मशाला में रहे थे (काल्पनिक नामों के साथ)। पीडब्लू-28 इब्राहिमभाई नासिरभाई जो ड्रीमलैंड होटल के मालिक हैं, पीडब्लू-32 सूर्यकांत चमनलाल, पीडब्लू-39 दादावाड़ी गुरुमंदिर धर्मशाला के प्रबंधक रामाजी रूपसिंग, पीडब्लू-40 जगदीशकुमार अमृतलाल सोनी, श्री पार्श्वनाथ भक्तिविहार जैन ट्रस्ट धर्मशाला के प्रबंधक, ने भी अलग-अलग तिथियों के लिए उपरोक्त तथ्य के संबंध में यही साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कैसे ए-1 और ए-2 फर्जी नामों के साथ धर्मशालाओं और होटलों में रहते थे। उन्होंने न्यायालय में दोनों आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार होने से पहले दोनों आरोपी 12.12.1994 से 23.01.1995 तक उपरोक्त तरीके से एक साथ रहे।

14. पुलिस गवाहों की गवाही में यह भी रिकार्ड में आया है कि हत्या के बाद शयनकक्ष साफ़ पाया गया और मृतक के शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने के प्रयास में बाथरूम में छिपाया गया था, जिसके लिए घर से सुई, जूट का धागा, प्लास्टिक की थैलियां, लोहे का ब्लेड आदि एकत्र किया गया था। यह भी रिकॉर्ड में

आया है कि दोपहर के आसपास ए-1 को ए-2 ने अपने हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए बाहर जाने की अनुमति दी थी। इस संबंध में पीडब्लू-4 डॉ. राजेंद्र हीरालाल शाह ने पट्टी बांधने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और संबंधित प्रविष्टियों को साबित किया है।

15. परिस्थितियों के आलोक में, रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य से, मेरी राय में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलकर्ता ने अपने ही भाई पीडब्लू-3 (शिकायतकर्ता) को मृतक के ठिकाने के बारे में गलत बयान देकर और पीडब्लू-34 अमी को शयनकक्ष से जुड़े बाथरूम (जहां शव छुपाया गया था) का उपयोग करने की अनुमति नहीं देकर अपराधी (ए-1) को बचाने के लिए गलत जानकारी दी है। इस प्रकार, उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप के संबंध में निचली अदालतों द्वारा उचित रूप से दोषी ठहराया गया था। ए-2 के अपराध के बारे में अपने स्वयं के निष्कर्ष के खिलाफ विचारण न्यायालय की कुछ टिप्पणियाँ इस न्यायालय के फैसले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, खासकर जब विचारण न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के फैसले में विलय हो जाता है जो हमारे समक्ष एक आक्षेपित निर्णय है और, ऐसे में, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से बरी नहीं किया जा सकता है। मैं इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत से सहमत हूं, जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति श्री एनवी रमना ने संदर्भित किया है, लेकिन अंततः प्रत्येक मामले में उस विशेष मामले के तथ्यों और सबूतों को निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए देखा जाना चाहिए कि उनमे किसी विशेष अपराध के घटक मौजूद हैं या नहीं।

16. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, मुझे निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि नहीं मिली है कि अपीलकर्ता पद्मिनी आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी है। हालाँकि, सजा के मामले में, उच्च

न्यायालय ने ए-2 (अपीलकर्ता) को अधिकतम सजा सुनाई है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिकॉर्ड से बताया कि अपीलकर्ता पहले ही मुकदमे/अपील की अवधि के दौरान दो साल से अधिक कारावास की सजा काट चुकी है। वह साठ वर्ष की है और घटना को तेईस वर्ष बीत चुके हैं। इन परिस्थितियों में, मेरा यह मानना है चूंकि ए-1 को आईपीसी की धारा 201 के तहत दी गई सजा उसी आरोप के संबंध में अंतिम रूप ले चुकी है, इसलिए उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ए-2 को बढ़ी हुई सजा देना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से ए-1 की तुलना में उक्त आरोप के संबंध में उसकी भूमिका पर विचार करते हुए।

17. अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ निचली अदालतों द्वारा दर्ज की गई सजा को बरकरार रखा जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम करके जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा दर्ज किया गया था।

आदेश

1. हमारे बीच असहमति को देखते हुए, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि मामले के निस्तारण के लिए एक उचित पीठ का गठन किया जा सके।

मामला बड़ी बेंच को प्रेषित किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।